आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

कहा- हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, चार घंटे से ज्यादा चला धरना, लगाए नारे

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं और हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते जैसे गगनभेदी नारों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर बुधवार को गूंज उठा। मप्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासंघ ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने करीब 4 घंटे से अधिक समय तक उग्र धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पंडाल में बैठीं महिला कार्यकर्ता हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लिए नारेबाजी करती दिखीं। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी

संगठन की अध्यक्ष ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत वे पिछले कई दशकों से शासन की हर छोटी-बड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर रही हैं। लाड़ली बहना योजना, बीएलओ ड्यूटी, जनगणना, और स्वास्थ्य सर्वे जैसे कई गैर-विभागीय काम भी उनसे जबरन कराए जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जाता है और काम न करने पर सेवा से हटाने या मानदेय काटने की धमकी दी जाती है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी मानसिक और आर्थिक असंतोष है।

नियमितीकरण सहित रखी अन्य मांगें

बुधवार को सौपे ज्ञापन में संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित किया जाने, सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन के लिए कम से कम 5000 रुपये मासिक पेंशन लागू किये जाने, केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने, मानदेय में की जा रही विसंगतियों और कटौतियों को बंद कर महंगाई के अनुपात में वेतन बढ़ाया जाने, सेवाकाल के दौरान कार्यकर्ता या सहायिका की मृत्यु होने पर उसकी बहू या बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने, कार्य के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को कम से कम 5 लाख रुपये की सांत्वना दिये जाने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन की आपूर्ति हर महीने सीधे केंद्रों पर ही सुनिश्चित कराई जाने, कार्यकर्ताओं की पदोन्नति में आड़े आने वाले आयु सीमा के बंधन को हटाकर वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिये जाने, महिला बाल विकास विभाग के मूल कार्यों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के शासकीय सर्वे और वीआईपी ड्यूटियों से मुक्त रखे जाने की मांग की गईहै। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर पर उनकी इन जायज मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में संपूर्ण काम बंद कर चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

पशु संगोष्ठी में पशुपालकों को मिली योजनाओं की जानकारी

नवभारत न्यूज

बैतूल। पशुपालन विभाग द्वारा क्षीरधारा ग्राम बाका खोदर विकासखंड शाहपुर में पशु संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पशुपालकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें शासकीय सुविधाओं से जोड़ना तथा आधुनिक पशुपालन को बढ़ावा देना था।

संगोष्ठी में उप संचालक पशुपालन डॉ. सुरजीत सिंह, कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के अधिकारियों ने पशुपालकों के साथ संवाद कर उन्नत पशुपालन, चारा प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य एवं आयवर्धन संबंधी विषयों पर जानकारी दी। अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान पात्र पशुपालकों का विभिन्न योजनाओं हेतु चयन भी किया गया। इनमें 40 पशुपालकों का पशु किसान क्रेडिट कार्ड, 15 पशुपालकों का पशु शेड निर्माण, 03 पशुपालकों का नाडेप कम्पोस्ट टैंक निर्माण तथा 03 पशुपालकों का चारा विकास प्रदर्शन योजना के लिए चयन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं से पशुपालकों को पशुओं के बेहतर रख-रखाव, जैविक खाद उत्पादन, उन्नत चारा विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

सारंगपुर एसडीएम मामले की जांच करेंगे कलेक्टर

हाईकोर्ट का कलेक्टर को आदेश, मामला राजगढ़ अभिभाषक और सारंगपुर एसडीएम विवाद का

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 03 जून, का. बीते माह सारंगपुर एसडीएम द्वारा कथित तौर पर राजगढ़ के एक अभिभाषक के साथ कहासुनी के मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को मामले में पूरे घटनाक्रम की जांच के निर्देश दिए है. मामला बीते 11-12 मइ का है जब सारंगपुर एसडीएम के विरूद्ध कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अभिभाषकों ने मोर्चा खोल दिया था. मामले में अभिभाषक से फोन पर अभद्रता करने और एफआईआर की धमकी का आरोप लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार रमेशचंद्र धाकड़ अधिवक्ता जिला न्यायालय राजगढ़ ने 13 मई को कलेक्टर को शिकायती आवेदन में कहा था कि सारंगपुर के एसडीएम द्वारा उनके साथ फोन पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार, अपमानजनक अमर्यादित भाषा और एफआईआर की धमकी दी है. अभिभाषक के अनुसार घटना 7 मई की है.

रमेशचंद्र धाकड़ ने किसी प्रकरण को लेकर एसडीएम सारंगपुर से फोन पर बात करनी चाही. एसडीएम ने फोन रिसीव नहीं किया.

लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अधिवक्ता रमेशचंद्र धाकड़ को फोन किया. रमेशचंद्र धाकड़ ने लिखित शिकायत में कहा कि उनसे एसडीएम ने परिचय पूछा जिस पर उन्होंने अपना नाम बताया और किसी प्रकरण के सर्च वारंट से संबंधित जानकारी चाही.

इस पर एसडीएम ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुमको इतनी अकल नहीं है, वारंट मेरे द्वारा जारी किया गया है, तुमने मुझे फोन कैसे लगाया. तुम जाहिल हो.

अधिवक्ता का कहना है कि उनके जीवन में यह पहला अवसर था जब वारंट के संबंध में प्रकरण मिला. मामले में अधिवक्ता ने अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए निष्पक्ष जांच के साथ कार्यवाही की मांग की गई है.

अब मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खण्डपीठ ने जांच के निर्देश दिए है. 7 दिनों में जिला कलेक्टर को पूरी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी.

दिन में 2 डिग्री उछला पारा शाम को फिर ठण्डी हवाएं

ब्यावरा 03 जून, का. बारिश और आंधी के साथ लोगों को राहत देते हुए नौतपे का समापन हुआ था. लेकिन नौतपे की समाप्ति के अगले ही दिन पारा 38 से उछलकर 40 डिग्री पहुंच गया. दिन में गर्म हवाओं के साथ चिलचिलाती धूप का एक बार फिर से सामना लोगों ने किया. लेकिन शाम को 7 बजे के बाद मौसम ने फिर से करवट ली और देखते ही देखते ठण्डी हवाओं का दौर शुरू हो गया. देर शाम काफी देर तक हवाएं चली और लोगों ने फिर से राहत की सांस ली. हालांकि मानसून में देरी के कारण फिर से आने वाले दिनों में पारे में उछाल की संभावना चताई जा रही है. चक्रवात के कारण इस प्रकार का क्लाउडी मौसम निर्धारित हो रहा है.

समिति सदस्यों और किसानों ने सौंपा ज्ञापन

चोपना। किसानों को खाद प्रदाय एवं किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सेवा सहकारी समिति सदस्यों, किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया कि किसानों को प्रति हेक्टेयर आवश्यकता से कम खाद दी जा रही है।

कई किसानों की तकनीकी कारणों से अभी तक फार्मर आईडी नहीं बन पाई है। जिसके कारण उनके टोकन जनरेट नहीं हो रहे है। प्राइवेट विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिम दाम में खाद बेच रहे है। पुनर्वासित परिवार, जिनको पुनर्वास विभाग द्वारा पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे परिवारों की संख्या 600 से अधिक है। उन्हें भूमि आवंटन प्रमाणपत्र दिया गया है, उनकी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, इसलिए सभी का खाद के लिए टोकन जनरेट नहीं हो रहे है। शासन के वर्तमान उर्वरक नीति नियमों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्तमान खाद वितरण नियम प्रणाली को निरस्त किया जाये। वर्ष 2025-26 खाद वितरण नियम व प्रक्रिया को पुनः लागू किया जाये। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद प्रदान की जाये एवं किसान क्रेडिट कार्डधारक किसानों की खाद एवं ऋण की लिमिट बढाई जाये।

ग्राम सलैया खुर्द में विस्थापन की कार्रवाई जारी

नागरिकों को मुआवजा वितरण करने के साथ उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा

नवभारत न्यूज

बंडा 3 जून. बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनरव्यवस्थापन और विस्थापन की कार्रवाई लगातार जारी है. परियोजना के तहत बन रहे उल्दन बांध क्षेत्र में आने वाले विभिन्न ग्रामों के नागरिकों को मुआवजा वितरण करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.

विस्थापित हो रहे परिवारों को ग्राम पनारी में व्यवस्थित रूप से बसाया जा रहा है. ग्राम सलैया खुर्द में पूर्व में तीन बार मुनादी कराकर ग्रामीणों को सूचित किया गया था. विभागीय टीम की मौजूदगी में विस्थापन की कार्रवाई करते हुए आवासीय संरचनाओं को हटाने का कार्य किया गया.

इस कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था और आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए विस्तृत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा. जिसमें एसडीएम बंडा श्रीमती आरती यादव, तहसीलदार मोहित जैन, एसडीओपी प्रदीप बाल्मिक, नायब तहसीलदार (बहरोल) जी सी राय, नायब तहसीलदार (बंडा) श्रीमती ज्योति राय, थाना प्रभारी बहरोल धर्मेंद्र सिंह सहित राजस्व निरीक्षक, पटवारी और कोटवार आदि मौजूद रहे. साथ ही जल संसाधन विभाग से परियोजना प्रबंधक अनिरुद्ध आनंद, एसडीओ धरमदास अहिरवार, आकाश सचान एवं जिज्ञासा जैन भी मौजूद रहे. ग्राम में पुनः मुनादी कराकर सभी प्रभावित ग्रामीणों से यह आग्रह किया गया है कि वे आगामी दो दिनों के भीतर नियमानुसार अपने घरों को खाली कर दें, ताकि मानसून के पहले समय पर विस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

5 से 21 जून तक चलेगा जनकल्याण एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान

नवभारत न्यूज

विदिशा. प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले जनकल्याण एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अभियान के सफल संचालन के लिए सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.बैठक में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वृहद पौधारोपण कार्यक्रम तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 के शुभारंभ की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई. स्वच्छता अभियान, 12 से 18 जून तक जनकल्याण शिविरों तथा 19 और 20 जून को प्राकृतिक खेती आधारित कार्यशालाओं की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई.

संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने झाड़ू लगाकर किया विरोध

- **हड़ताल के दूसरे दिन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर**
- **160 से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लटके ताले**

नवभारत न्यूज

सीहोर 3 जून. संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जिले के 160 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहे, मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं और मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ा.

हड़ताल शुरू होने के बाद सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया द्वारा संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी कर तत्काल ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए थे. इसका उल्टा असर देखने को मिला जो कर्मचारी पहले आंदोलन में शामिल नहीं थे, वे भी विरोध स्वरूप हड़ताल में शामिल हो गए.जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले रहे, लेकिन पर्ची बनाने, दवा वितरण, इंजेक्शन और ड्रिप लगाने वाले कर्मचारी अनुपस्थित रहे. ऐसे में चिकित्सकों को स्वयं पर्चे बनाकर दवाइयां वितरित करनी पड़ीं. टीकाकरण सहित कई नियमित सेवाएं प्रभावित रहीं.

बुधवार को संविदा कर्मचारियों ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा टाउन हॉल के बाहर धरना देकर नारेबाजी की.जिलाध्यक्ष हरिओम मेवाड़ा ने कहा कि कर्मचारियों ने सूचना देकर आंदोलन शुरू किया है और वे नियमितीकरण सहित अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. हड़ताल का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दिया. बरखेड़ा हसन और खजूरिया कासम सहित कई उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके मिले. ग्रामीणों का कहना है कि दो दिनों से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं, जिससे उन्हें निजी क्लीनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है.

मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी

नवभारत न्यूज, टीकमगढ़।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2023 में संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई नीति आज तक एनएचएम के संविदाकर्मियों पर लागू नहीं की गई है।

जिला अध्यक्ष नितिन तिवारी ने बताया कि उनकी समस्याओं और मांगों की जानकारी कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। कंचन तिवारी,जिला अस्पताल अध्यक्ष ने बताया कि आज हम सभी संविदा कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप शासन की नीतियों और कथित कुरीतियों का प्रतीकात्मक दहन कर नाराजगी जताई। संविदाकर्मियों का आरोप है कि उन्हें कम वेतन में लगातार सेवाएं देनी पड़ती हैं, जबकि मेडिकल लीव सहित कई मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।

खेल गतिविधियों के तहत दिया गया प्रशिक्षण

नवभारत न्यूज, टीकमगढ़।

पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में एक मई से दो जून तक मलखम्ब, फुटबॉल, कराते, साफ्टबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, तैराकी, जुम्बा एवं पेंटिंग खेल गतिविधियो में प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

शिविर कें अतिंम सप्ताह में समस्त खेल गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों की प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें तैराकी खेल की प्रतियोगिता ब्लू स्काई स्विमिंग पूल में आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रविन्द्र श्रीवास्तव, एनएस राय एवं काषीराम साहू उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में फ्री-स्टाईल, वटर फ्लाई, बैक स्टोक विधाओं में खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा अतिथियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।

कृषकों को मिलेगा नि :शुल्क बीज

नवभारत न्यूज

टीकमगढ़। मप्र शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा तिलहन फसलों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मिशन ऑन इडीबल ऑयल योजना अंतर्गत घटक बीज वितरण अनुदान के माध्यम से कृषकों को नि:शुल्क बीज वितरण किया जायेगा। पंजीयन के आधार पर प्रति प्रदर्शन अनुदान में बीज वस्तु के रूप में किसानों को उपलब्ध कराकर कैफेटेरिया अनुसार कृषकों के द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर अनुदान भुगतान किया जायेगा।

ढाक के तीन पात | **कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद जिले के सैकड़ों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन का रास्ता साफ**

अंतत : सीएमएचओ शोभा पटेल ही जारी करेंगी वेतन

आंदोलन स्थगित, काम पर लौटेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 03 जून, का. बीते 25 मई से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर वेतन संकट, आहरण की अनिश्चितता और हड़ताल की गतिविधियों को विराम मिला है. अपर कलेक्टर के आदेश के बाद संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने राहत की सांस ली है. आदेश के मुताबिक सीमएचओ डॉ शोभा पटेल को वेतन आहरण संवितरण के अधिकार दिये गये है. इससे अब जल्द ही कर्मचारियों का वेतन जारी हो जायेगा.

उल्लेखनीय है कि बीते 30 अप्रैल को लोकायुक्त कार्यवाही के बाद सीएमचओ डॉ पटेल को शाजापुर तबादला कर दिया था. इसके बाद जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ एल.पी.भकोरिया को प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी नियुक्त किया था. इसी आधार पर डॉ भकोरिया की आईडी मेंपिग जिला कोषालय में की गई थी लेकिन इसी बीच 05 मई को उच्चन्यायालय इन्दौर खंडपीठ के आदेश पर डॉ शोभा पटेल को स्थगन देते हुये पुन: राजगढ़ पदस्थापना दे दी गई.

17 अप्रैल से इस तरह चला घटनाक्रम

- 17 अप्रैल को सीएमएचओ डॉ शोभा पटेल को लोकायुक्त ने कथित तौर पर रिश्वत मामले में ट्रेप किया.
- 22 अप्रैल को उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया.
- 27 अप्रैल को डॉ शोभा पटेल का ट्रांसफर शाजापुर किया गया.
- 30 अप्रैल को जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ एलपी भकोरिया को कलेक्टर द्वारा प्रभारी सीएमएचओ का चार्ज दिया.
- 05 मई को लोकायुक्त कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने डॉ पटेल को स्टे देते हुए पुन: राजगढ़ भेजा.
- 09 मई को डॉ भकोरिया से चार्ज वापस लिया गया.
- 02 जून को संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए
- 03 जून को वेतन आहरण एवं संवितरण के अधिकार सीएमएचओ को दिए

हड़ताल के बाद जागा प्रशासन

संविदा स्वास्थय कर्मचारियों द्वारा अप्रैल और मई माह का वेतन रुकने के बाद 25 मई को प्रशासन को ज्ञापन देकर चेतावनी जारी की थी. 01 जून तक वेतन का रास्ता साफ नहीं होने पर गत दिनों कर्मचारियों ने उग्र रास्ता अपना लिया था जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और कलेक्टर ने हस्तक्षेप करते हुये डॉ शोभा पटेल को जिले में स्वास्थय कर्मचारियों के वेतन के आहरण संवितरण के अधिकार सौंप दिये है.

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

गुना। जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी नियमितीकरण सहित 8 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलन के दूसरे दिन, 3 जून 2026 को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान कर्मचारियों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए 'प्यासो प्याऊ' लगाई और आमजन को पानी पिलाकर सरकार को संदेश दिया कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो आगामी चुनाव में वे सरकार को पानी पिला देंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश भार्गव ने बताया कि संविदा कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं हो पाया है। उन्होंने याद दिलाया कि 30 जनवरी 2025 को भोपाल के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सिंह यादव ने नियमितीकरण की घोषणा की थी। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि वर्ष 2023 की नीति के तहत एनपीएस, स्वास्थ्य बीमा, 10 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता, पीबीआई का समायोजन, वेतन विसंगति को दूर करना, नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश की पात्रता, समान कार्य-समान वेतन लागू किया जाए और सार्थक ऐप की बाध्यता को तत्काल समाप्त किया जाए। संविदा कर्मचारियों की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण गुना जिले के सभी विकासखंडों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों तक कामकाज ठप होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।